



Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 145-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 18, 2017 (SRAVANA 26, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अगस्त, 2017

संख्या 71/एसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शवित्रों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में, उपनियम (4) में, “जिससे संयुक्त उद्ग्रहण के विकल्प का प्रयोग किया जाता है” शब्दों के बाद, “से नब्बे दिन की अवधि के भीतर” शब्द रखें जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 17 में, उपनियम (2) में, “उक्त प्ररूप भरे जाने” शब्दों के बाद, “या भारत सरकार, विदेश मंत्रालय से अनुशंसा प्राप्त होने के” शब्द रखें जाएंगे और 22 जून, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 40 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा जुलाई 2017 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्,-
 - “(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने हेतु पात्र होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा, अधिसूचना द्वारा बढ़ाई जाएं, प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01 में, सामान्य पोर्टल पर, इलैक्ट्रोनिक रूप से, इस प्रभाव की घोषणा करेगा कि वह यथापूर्वकत इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने का पात्र है:
- परंतु केंद्रीय कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।”।
- उक्त नियमों में, नियम 61 में, उपनियम (5) में, “ऐसा विनिर्दिष्ट कर सकता है कि” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी रीति और शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिनके अध्यधीन” शब्द तथा विहन प्रतिस्थापित किये जाएंगे तथा जुलाई 2017 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किया गये समझे जायेंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 87 में,

(क) उपनियम (2) में,

- (i) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ii) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्—

“परंतु सामान्य पोर्टल पर सृजित किया गया प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में चालान पंद्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा:

परंतु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से आनेलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं का प्रदाय करने वाला व्यक्ति बोर्ड की भुगतान प्रणाली अर्थात् उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलेक्ट्रोनिक लेखांकन प्रणाली के माध्यम से भी बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तिथि से ऐसा कर सकता है।”;

(ख) उपनियम (3) में, द्वितीय परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं का प्रदाय करने वाला व्यक्ति, बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तिथि से विश्वव्यापी इंटर बैंक वित्तीय दूरसंचार भुगतान नेटवर्क के लिए सोसाइटी के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण के माध्यम से उपनियम (2) के अधीन भी निष्क्रेप कर सकता है।”।

7. उक्त नियमों में, नियम 103 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम जुलाई 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्—

“103 सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में ऐसे अधिकारियों जो संयुक्त आयुक्त की पदवी से नीचे के न हों, को नियुक्त करेगा।”।

8. उक्त नियमों में, “प्ररूप जीएसटी आरईजी-01” में, ‘रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने सम्बन्धी अनुदेश’ शीर्ष के अधीन, क्रम संख्या 15 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या रखी जायेगी, अर्थात्—

“16 प्रदायकर्ताओं के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले सरकारी विभाग बैंक खाते के ब्यारे प्रस्तुत नहीं करेगे।”।

9. उक्त नियमों में, विद्यमान “प्ररूप जीएसटी आरईजी-13” के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 22 जून, 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्—

प्रस्तुत जीएसटी आरईजी-13

[देखिए नियम 17]

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्रस्तुत
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र – जिला –

भाग क

(i)	संस्था का नाम	
(ii)	संस्था का स्थायी लेखा संख्या (अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं को लागू नहीं होता है)	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी लेखा संख्या (अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं को लागू नहीं होता है)	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाईल नंबर (+91)	

भाग ख

1.	संस्था की किस्म (कोई एक चुनें)	संयुक्त राष्ट्र	दूतावास	अन्य व्यवित
2.	देश			
2क	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश (यदि लागू हो)		पत्र संख्या	तिथि
3.	अधिसूचना के ब्यौरे		अधिसूचना संख्या	तिथि
4.	राज्य में संस्था का पता			
	भवन संख्या / फ्लैट संख्या		मंजिल संख्या	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क / गली	
	शहर / कस्बा / गाँव		जिला	
	ब्लॉक / तालुका			
	अक्षांश		देशान्तर	
	राज्य		पिन कोड	
	संपर्क के लिए जानकारी			
	ईमेल पता		टेलीफोन नंबर	
	फैक्स नंबर		मोबाईल नंबर	
7.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, यदि लागू हों			
	विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	नाम			
	फोटो			
	पिता का नाम			
	जन्म की तिथि	दिन / मास / वर्ष	लिंग	<पुरुष, महिला, अन्य>
	मोबाईल नंबर		ईमेल पता	

	टेलीफोन नंबर						
	पदनाम/ हैसियत				निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)		
	स्थायी लेखा संख्या (अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं को लागू नहीं होता है)				आधार संख्या (अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं को लागू नहीं होता है)		
	क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हाँ/ नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशियों के मामले में)				
	घर का पता						
	भवन संख्या/ फ्लैट संख्या				मंजिल संख्या		
	परिसर/ भवन का नाम				सड़क/ गली		
	नगर/ शहर/ गाँव				जिला		
	ब्लॉक/ तालुका						
	राज्य				पिन कोड		
8.	बैंक खाता बैंयौरे (यदि आवश्यक हो तो और जोड़ें)						
	खाता संख्या				खाते का प्रकार		
	आईएफएससी				बैंक का नाम		
	शाखा का पता						
9.	अपलोड किए गए दस्तावेज						
	प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/ मुख्तारनामा भी है, को अपलोड किया जाएगा।						
	या						
	समुचित अधिकारी, जिसने आवेदक से दस्तावेज साक्ष्य एकत्र किए हैं ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/ दूतावास इत्यादि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/ मुख्तारनामा भी है, अपलोड किया जाएगा और इसे संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/ दूतावास इत्यादि को सृजित और आंबटित विशिष्ट पहचान संख्या के साथ लिंक किया जाएगा।						
11.	सत्यापन						
	मैं सत्यापन से यहा अभिपुष्टि करता हूं कि इसमें उपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।						

स्थान:

(हस्ताक्षर)

तिथि:

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

या

स्थान:

(हस्ताक्षर)

तिथि:

समुचित अधिकारी का नाम:

पदनाम:

अधिकारिता:

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सबःप्रेरणा से अनुदत्त किया जा सकता है।
- सामान्य पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिकी रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य ढंग के माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है।
- संबंधित संस्था द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के ब्यौरों को आवेदन में “प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे” के सामने भरा जाना चाहिए।
- स्थायी लेखा संख्यांक/आधार अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं के लिए लागू नहीं होगा।

10. उक्त नियमों में, “प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1” में, क्रम संख्या 7 में,—

- मद (क) में, “और 140(6)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “140(6) और 140(7)” अंक, कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे तथा जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे;
- मद (ख) में,—
 - “धारा 140(5)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के बाद, “और धारा 140(7)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जायेंगे तथा जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायेंगे;
 - खाना 1 में, विद्यमान शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्—

“प्रदायकर्ता या इनपुट सेवा वितरक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक”;
 - खाना 8 में, शीर्ष में, “पात्र शुल्क और कर” शब्दों के बाद, “(केन्द्रीय कर)” कोष्ठक और शब्द रखे जायेंगे तथा जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से रखे गये समझे जायेंगे।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th August, 2017

No.71/ST-2 - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2017.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in rule 3, in sub-rule (4), for the words “sixty days”, the words “ninety days” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 17, in sub-rule (2), after the words, “said form”, the words “or after receiving a recommendation from the Ministry of External Affairs, Government of India” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 22nd June, 2017.
4. In the said rules, in rule 40, in sub-rule (1), for clause (b), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

(b) the registered person shall within a period of thirty days from the date of becoming eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18, or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf, shall make a declaration, electronically, on the common portal in **FORM GST ITC-01** to the effect that he is eligible to avail the input tax credit as aforesaid:

Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”;

5. In the said rules, in rule 61, in sub-rule (5), for the words “specify that”, the words “specify the manner and conditions subject to which the” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017.

6. In the said rules, in rule 87,-

(a) in sub-rule (2),
(i) for the sign “.” existing at the end, the sign “;” shall be substituted;
(ii) after sub-rule (2), the following provisos shall be added, namely:-

“Provided that the challan in FORM GST PMT-06 generated at the common portal shall be valid for a period of fifteen days:

Provided further that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also do so through the Board’s payment system namely, Electronic Accounting System in Excise and Service Tax from the date to be notified by the Board.”;

(b) in sub-rule (3), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided further that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also make the deposit under sub-rule (2) through international money transfer through Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication payment network, from the date to be notified by the Board.”.

7. In the said rules, for rule 103, the following rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

“103. The Government shall appoint officers not below the rank of Joint Commissioner as member of the Authority for Advance Ruling.”.

8. In the said rules, in “FORM GST REG-01” under the heading ‘Instructions for submission of Application for Registration’, after serial number 15, the following serial number shall be inserted, namely:-

“16. Government departments applying for registration as suppliers may not furnish Bank Account details.”.

9. In the said rules, for “FORM GST REG-13”, the following Form shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 22nd June, 2017 namely:-

“FORM GST REG-13*[See Rule 17]***Application/Form for grant of Unique Identity Number (UIN) to UN Bodies/ Embassies /others****State /UT –****District –****PART A**

(i)	Name of the Entity	
(ii)	Permanent Account Number (PAN) of entity (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	
(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	PAN of Authorised Signatory (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	
(v)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vi)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

PART B

1.	Type of Entity (Choose one)	UN Body	Embassy	Other Person
2.	Country			
2A.	Ministry of External Affairs, Government of India' Recommendation (if applicable)	Letter No.	Date	
3.	Notification details	Notification No.	Date	
4.	Address of the entity in State			
	Building No./Flat No.	Floor No.		
	Name of the Premises/Building	Road/Street		
	City/Town/Village	District		
	Block/Taluka			
	Latitude	Longitude		
	State	PIN Code		
	Contact Information			
	Email Address	Telephone number		
	Fax Number	Mobile Number		

7.	Details of Authorized Signatory, if applicable			
	Particulars	First Name	Middle Name	Last name
	Name			
	Photo			
	Name of Father			
	Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
	Mobile Number		Email address	
	Telephone No.			
	Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
	PAN (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)		Aadhaar Number (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	
Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)		
Residential Address				
Building No./Flat No.		Floor No.		
Name of the Premises/Building		Road/Street		
Town/City/Village		District		
Block/Taluka				
State		PIN Code		
8	Bank Account Details (add more if required)			
	Account Number		Type of Account	
	IFSC		Bank Name	
	Branch Address			
9.	Documents Uploaded <i>The authorized person who is in possession of the documentary evidence shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorizing the applicant to represent the entity.</i>			

	<p>Or</p> <p><i>The proper officer who has collected the documentary evidence from the applicant shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorizing the applicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and link it along with the UIN generated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc.</i></p>
11.	<p>Verification</p> <p><i>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</i></p>

Place:

(Signature)

Date:

Name of Authorized Person:

Or

Place:

(Signature)

Date:

Name of Proper Officer:

Designation:

Jurisdiction:

Instructions for submission of application for registration for UN Bodies/ Embassies/others notified by the Government.

- Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically.
- Application shall be filed through Common Portal or registration can be granted suo-moto by proper officer.
- The application filed on the Common Portal is required to be signed electronically or through any other mode as specified by the Government.
- The details of the person authorized by the concerned entity to sign the refund application or otherwise, should be filled up against the “Authorised Signatory details” in the application.
- PAN / Aadhaar will not be applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act.

10. In the said rules, in FORM GST TRAN-1 in serial number 7,-

- (i) in item (a), for the word, figures and brackets “and 140 (6)”, the figures, brackets and word “, 140 (6) and 140 (7)” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017;
- (ii) in item (b), -
 - (a) after the word, figures and brackets, “section 140 (5)”, the words, figures and brackets “and section 140(7)” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017;
 - (b) for column heading 1, the column heading “registration number of the supplier or input service distributor” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017;
 - (c) in the heading of column 8, after the words “Eligible duties and taxes”, the brackets and words “(central taxes)” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.